



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 24, 2017/कार्तिक 2, 1939  
No. 279] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 24, 2017/KARTIKA 2, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2017

सं. 34/2015-2020

**विषय:** निर्यात दायित्व विस्तार और अग्रिम प्राधिकार पत्र की क्लबिंग हेतु एककालिक छूट के संबंध में।

फा. सं. 01/94/180/186/ए एम-18/पीसी-4.—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 2.04 और 2.58 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार नीतिगत छूट समिति (पीआरसी) की सिफारिश के आधार पर जनहित में एतद्वारा निर्यात दायित्व अवधि बढ़ाने तथा अग्रिम प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग के प्रावधानों में निम्नलिखित एककालिक छूट प्रदान करते हैं:—

## 1. अग्रिम लाइसेंसों/प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की सुविधा:

विदेश व्यापार नीति 2002-2007 और 2004-09 के तहत जारी अग्रिम लाइसेंसों/प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग के लिए प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के पैरा 4.38 (i) की एककालिक छूट की एतद्वारा अनुमति दी जाती है क्लबिंग हेतु अनुरोध विहित दस्तावेजों के साथ संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को एएनएफ-4ग में किया जाएगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के पैरा 4.38 के अनुसार मामलों को प्रोसेस करेगा। ऐसे आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 31.03.2018 होगी। दिनांक 31.03.2018 के बाद क्लबिंग हेतु क्षेत्रीय प्राधिकरण में प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा मामलों को 31.05.2018 को अथवा उससे पहले ही एचबीपी के पैरा 4.49 के तहत अथवा न्यायनिर्णय कार्यवाही आरंभ करके नियमित किया जाएगा।

उन प्राधिकार पत्रों के संबंध में किसी क्लबिंग की अनुमति नहीं होगी जिनमें क्षेत्रीय प्राधिकारी को गलत जानकारी/जालसाजी की सूचना मिली है। इसके अलावा, उन प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की अनुमति नहीं होगी जहां क्षेत्रीय प्राधिकारी/सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा ईओडीसी/मोचन पत्र पहले ही जारी कर दिया गया है अथवा न्यायनिर्णयन आदेश पहले ही जारी कर दिया गया है।

## 2. निर्यात दायित्व अवधि का विस्तार:

नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन निर्यात दायित्व ईओ अवधि बढ़ाने के लिए एककालिक छूट प्रदान की जाती है।

विदेश व्यापार नीति, 2002-07, विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 के तहत जारी अग्रिम लाइसेंसों/प्राधिकार पत्रों तथा विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के तहत दिनांक 05.06.2012 से पहले जारी अग्रिम प्राधिकार पत्रों के अंतर्गत किए गए निर्यात निम्नलिखित निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्यात दायित्व अवधि के विस्तार के जरिए नियमित किया जाएगा:

क. जहां निर्यात अग्रिम लाइसेंसों/प्राधिकार पत्रों के जारी होने की तारीख से 36 महीनों के भीतर किए गए हैं इसे उन मामलों जहां दिनांक 30.06.2003 की नीतिगत परिपत्र सं० 9 के तहत प्राधिकार पत्र जारी किए गए अथवा एचबीपी 2004-09/एचबीपी 2009-2014 के परिशिष्ट-30क के तहत मद शामिल हैं, को छोड़कर किसी संरचना शुल्क पर जोर दिए बिना नियमित किया जाएगा।

ख. 36 माह के पश्चात् परन्तु 48 माह के भीतर किए गए निर्यातों को निम्नलिखित संरचना शुल्क का भुगतान करने पर नियमित किया जाएगा:

1. 36 माह के पश्चात् परन्तु 42 माह के भीतर किए गए निर्यात को एफओबी मूल्य के 0.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से।

2. 42 माह के पश्चात् परन्तु 48 माह के भीतर किए गए निर्यातों के एफओबी मूल्य के 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से।

ग. ऐसे प्राधिकार पत्रों, जो नीतिगत परिपत्र सं. 9 दिनांक 30.06.2003 के तहत जारी किए गए हैं अथवा प्रक्रिया पुस्तक 2004-09/प्रक्रिया पुस्तक 2009-14 के परिशिष्ट-30क के तहत शामिल निविष्टियों के लिए:

निर्यात दायित्व अवधि का विस्तार निम्नलिखित संरचना शुल्क के भुगतान पर नियत प्रारंभिक निर्यात दायित्व अवधि के आधे के बराबर किया जा सकता है:

1. यदि प्रारंभिक निर्यात दायित्व अवधि के भीतर किया गया निर्यात नियत निर्यात दायित्व के 50 प्रतिशत से अधिक हो, तो एफओबी मूल्य के 0.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से।

2. यदि प्रारंभिक निर्यात दायित्व अवधि के भीतर किया गया निर्यात नियत निर्यात दायित्व के 50 प्रतिशत से कम हो तो एफओबी मूल्य के 1 प्रतिशत प्रति माह की दर से।

घ. निर्यात दायित्व अवधि के विस्तार हेतु संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारियों को अनुरोध दिनांक 31.03.2018 को अथवा इससे पहले किया जाना चाहिए। इस सार्वजनिक सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2018 के पश्चात प्राप्त किसी भी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

ड. केवल ऐसे पोतलदान बिल जिनमें संबंधित फाइल संख्या/अग्रिम प्राधिकार पत्र संख्या हो, को शामिल किया जाएगा। किसी भी मुक्त पोतलदान बिलों को शामिल किए जाने की अनुमति नहीं होगी।

च. ऐसे प्राधिकार पत्रों के संबंध में निर्यात दायित्व का कोई विस्तार नहीं किया जाएगा जहां क्षेत्रीय प्राधिकारी के ध्यान में कोई मिथ्या प्रस्तुति/धोखाधड़ी आई हो। इसके अतिरिक्त ऐसे प्राधिकार पत्रों का कोई विस्तार नहीं किया जाएगा जिनमें क्षेत्रीय प्राधिकारी/सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा न्यायनिर्णयन आदेश पहले ही पारित किया गया है।

#### **इसा सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:**

विदेश व्यापार नीति 2002-07 और विदेश व्यापार नीति 2004-09 के दौरान जारी अग्रिम प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग हेतु एकबारगी छूट प्रदान की गई है। विदेश व्यापार नीति 2002-07, विदेश व्यापार नीति 2004-09 के तहत जारी अग्रिम प्राधिकारों और विदेश व्यापार नीति 2009-14 के तहत दिनांक 05.06.2012 से पहले जारी अग्रिम प्राधिकारों की निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार हेतु भी एकबारगी छूट प्रदान की गई है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

### **MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

#### **PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 24th October, 2017

**No. 34/2015-2020**

**Sub: Onetime relaxation for EO extension and clubbing of Advance Authorisations - reg**

**F. No. 01/94/180/186/AM18/PC-4.**—In exercise of powers conferred under Para 2.04 and 2.58 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade on recommendation of Policy Relaxation Committee (PRC), in public interest, hereby makes the following one time relaxations in the provisions of extension of export obligation period and clubbing of advance Authorisations.

## 1. Facility of Clubbing of Advance Licences/Authorisations:

Onetime relaxation of Para 4.38(i) of Handbook of Procedures 2015-2020, for clubbing of Advance licenses/Authorisations issued under Foreign Trade Policy 2002-2007 and 2004-09 is hereby permitted. Request for clubbing shall be made in ANF-4C to the respective RAs along with prescribed documents. RA shall process the cases as per Para 4.38 of Handbook of Procedures 2015-2020. **The last date for submission of such application shall be 31.3.2018.** Any applications received in RA, after 31.3.2018 shall not be entertained for clubbing and case shall be regularized either under Para 4.49 of HBP or by initiation of adjudication proceedings on or before 31.05.2018 positively.

No clubbing shall be permitted in respect of Authorisations where misrepresentation / fraud have come to the notice of RA. Further, no clubbing of Authorisations, where EODC/redemption letter has already been issued or adjudication orders have already been passed by RA/Customs Authority, shall be permitted.

## 2. Extension of Export Obligation Period:

Onetime relaxation is provided for extending Export Obligation (EO) period subject to the conditions specified below.

Exports made under Advance Licences/Authorisations issued under Foreign Trade Policy 2002-07, Foreign Trade Policy 2004-2009 and Advance authorisations issued prior to 5.6.2012 under Foreign Trade Policy 2009-14 shall be regularized by way of extension of Export Obligation Period, as per the procedure prescribed below:

- a. Where exports have been made within 36 months from the date of issue of Advance Licences/ Authorisations, same shall be regularized without insisting for any composition fee, except the cases where authorizations issued under Policy circular No-9 dated 30.6.2003/ or items covered under Appendix-30 A of HBP 2004-09/ HBP 2009-14.
- b. For the exports made after 36 months but within 48 months shall be regularized on payment of composition fees as follows:
  - i. @ 0.5% per month of FOB value of exports made after 36 months but within 42 months
  - ii. @ 1% per month of FOB value of exports made after 42 months but within 48 months
- c. For Authorisations issued under Policy circular No-9 dated 30.6.2003 or inputs covered under Appendix-30A of HBP 2004-09 / HBP 2009-14:  
Extension of export obligation period can be granted for a period equivalent to half of the stipulated initial export obligation period on payment of composition fee as follows:
  - i. @0.5% per month of FOB if exports made within initial export obligation period is more than 50% of stipulated EO.
  - ii. @ 1% per month of FOB if exports made within initial export obligation period is less than 50% of stipulated EO.
- d. Request for extension of Export obligation period shall be filed in respective RAs, **on or before 31.3.2018.** Any applications received after 31.3.2018 shall not be considered as per this Public notice.
- e. Only shipping bills which bear file number/ Advance Authorisation number in question shall be taken into account. No free shipping bills shall be allowed to be accounted.
- f. No extension in EO would be allowed in respect of Authorisations where misrepresentation / fraud have come to the notice of RA. Further, no extension of Authorisations, where adjudication orders have already been passed by RA/Customs Authority, shall be permitted.

**Effect of this Public Notice:**

One time relaxation is provided for Clubbing of advance Authorisations issued during foreign trade policy 2002-07 and foreign trade policy 2004-09. One time relaxation is provided for extension of export obligation period of Advance authorizations issued under Foreign Trade Policy 2002-07, Foreign Trade Policy 2004-2009 and Advance Authorisations issued prior to 5.6.2012 under foreign trade Policy 2009-14.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade